



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 23 जून, 2020/02 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मई, 2020

संख्या: रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर.एण्ड.पी.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, हिमाचल प्रदेश में डाटा एंट्री, ऑपरेटर,

आपातकालीन प्रचालन केन्द्र, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, डाटा एंट्री, ऑप्रेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव (राजस्व)।

उपाबन्ध—‘क’

हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग में डाटा एंट्री ऑप्रेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए
भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—डाटा एंट्री ऑप्रेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र
2. **पद (पदों) की संख्या.**—03 (तीन)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग— III (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान: रुपए पे बैण्ड 5910—20200 /— जमा रुपए 1900 /—ग्रेड पे
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्योरे के अनुसार 7810 /— रुपए प्रतिमास
5. **चयन पद अथवा अचयन पद:** लागू नहीं
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु:** 18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों

में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ) : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा पास की हो।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या डिम्ड विश्वविद्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा/डोएक सोसाइटी/ राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (नायलट) से "ओ" स्तर का कोर्स।

(iii) हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान/से दसवीं और 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों पर लागू नहीं होगी।

(ख) वांछनीय अर्हता(एँ) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा आधार पर, सेवावृत्ति के आधार पर नियुक्ति पर अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः नियोजन पर और आमेसन पर कोई परीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, हिमाचल प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र को रुपए 810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए 234/- की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या

यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपए 7810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रुपए 234/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट—I

1.	लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:—	15 अंक

(i) भर्ती और प्रोन्नति में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता	=2.5 अंक
[शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 × 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे]।	
(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित	= 01 अंक
(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब का कोई सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा	= 01 अंक
(iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है	= 01 अंक
(v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन	= 01 अंक
(vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता	= 01 अंक
(vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बीपीएल कुटुम्ब	= 02 अंक
(viii)विधवा/तलाकशुदा/अकिंचल/एकल महिला	= 01 अंक
(ix) इकलौती पुत्री/अनाथ	= 01 अंक
(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण	= 01 अंक
(xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	= 01 अंक

परिशिष्ट –“II”

डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र वर्ग-III और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ के माध्यम से निष्पादित की जानी वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और ‘प्रथम पक्षकार’ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपातकालीन प्रचालन केन्द्र के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए

द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस अर्थात्स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रुपये 7810/- प्रतिमास होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो। ;
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें

परिसंकटमयस्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

2.
.....
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.
(नाम व पूरा पता)
2.
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019 /R&P dated 16-5-2020 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE (DISASTER MANAGEMENT CELL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th May, 2020

No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019/R&P.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Data Entry Operator, Emergency Operation Centre, Cass-III (Non Gazetted) in

the Department of Revenue (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management Cell), Data Entry Operator, Emergency Operation Centre, Class-III, (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,
ONKAR CHAND SHARMA
Principal Secretary (Revenue).

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATORS EMERGENCY OPERATION CENTRE, CLASS- III, (NON GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF REVENUE, (DISASTER MANAGEMENT CELL), HIMACHAL PRADESH.

- 1. Name of the Post.**—Data Entry Operator, Emergency Operation Centre.
- 2. Number of Post (Posts).**—03 (Three)
- 3. Classification.**—Class-III (Non Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—*Pay Scale for regular incumbent(s)* : (i) Pay Band Rs. 5910-20200/- + Rs. 1900/- Grade Pay
(ii) *Emoluments for Contract Employee(s)* : Rs. 7810/- P.M. as per details given in Column No.15-A.
- 5. Whether “selection” post or non-selection post.**—Not applicable.
- 6. Age for direct recruits.**—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government. of H.P. including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other backward categories and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) *Essential Qualification(s)* : (i) 10+2 examination passed from a recognized Board or University.

(ii) Diploma of atleast one year duration in Data Entry Operator / Computer Application / Computer Programming from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University / “O” Level Course from DOEACC Society / National Institute of Electronics & Information technology (NIELT).

(iii) Must have passed Matriculation & 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh.

Provided that this condition shall not apply to Bonafied Himachalis.

(b) *Desirable qualification* : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable

Educational Qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis re-employment and absorption.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment, transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) *Departmental Promotion Committee* : “Not applicable”.

(b) *Departmental Confirmation Committee* : “As may be constituted by the Government from time to time”.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus

etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Data Entry Operator, Emergency Operation Centre in the Department of Revenue, Disaster Management Cell, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC* : The Director, Disaster Management Cell, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Data Entry Operator Emergency Operation Centre appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director, Disaster Management Cell will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh, Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be

entitled for increase in contractual amount Rs. 234/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be reexamined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

1.	WRITTEN EXAMINATION (Percentage of Marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks).			85 Marks
2.	Evaluation of candidate to be made in following inner:—			15 Marks
	(i)	Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rule (Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025 For example, an individual has secured 50% marks in the required education qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)	2.5 Marks	
	(ii)	Belonging to notified Backward area or Panchayats, as the case may be.	01 Marks	
	(iii)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	01 Marks	
	(iv)	Non-Employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government /Semi Government services.	01 Marks	
	(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.	01 Marks	
	(vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National level sports competitions.	01 Marks	
	(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time.	02 Marks	
	(viii)	Widow/divorced/destitute/single woman	01 Marks	
	(ix)	Single daughter/Orphan	01 Marks	
	(x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution.	01 Marks	
	(xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Government/ /Semi Government Organization relating to the post applied for (0.5 Marks only for each completed year).	2.5 Marks	

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE DATA ENTRY OPERATORS, EMERGENCY OPERATION CENTRE AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR, DISASTER MANAGEMENT CELL.

This agreement is made on this.....day of.....in the yearbetween Sh./Smt..... s/o/d/o r/o contract appointee, (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Disaster Management Cell (hereinafter called the “SECOND PARTY”).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Data Entry Operators Emergency Operation on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Data Entry Operator Emergency Operation Centre for a period of one year commencing on day ofand ending on the day ofIt is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. onand information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended:

2. The Contractual amount of the First Party will be Rs. 7810/- per month.
3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall

- not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.
 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1.

(Name and full address)

Signature of the FIRST PARTY

2.

(Name and full address)

Signature of the SECOND PARTY

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जून, 2020

संख्या:आई.पी.एच.-बी(ई)5-18/2019-सोलन.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़ोग तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में कोटला त्रिमली रोड़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलेक्टर/समाहर्ता (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
सोलन	सोलन	बड़ोग	41/1	02-05

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (जल शक्ति)।

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जून, 2020

संख्या:आई.पी.एच.-बी(एच)1-3/2015-सोलन-1.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बगुड़ तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में कोटला त्रिमली रोड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलेक्टर/समाहर्ता (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
सोलन	सोलन	बगुड़	10/1	01-02

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (जल शक्ति)।

In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Kavneesh Bhardwal aged 18 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Sapahal, P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Pooja Kumari aged 19 years d/o Ramesh Chand, r/o Village Kuthiana, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
.. Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Kavneesh Bhardwal aged 18 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Sapahal, P.O. Chouri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Pooja Kumari aged 19 years d/o Ramesh Chand, r/o Village Kuthiana, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-05-2020. The objection received after 30-06-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-05-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

SHILPI BEAKTA, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 12/NT/20

Smt. Choephel Kalsang s/o Late Phuntsok, r/o H. No. 540, Tipa Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Choephel Kalsang s/o Late Phuntsok, r/o H. No. 540, Tipa Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 26-02-1963 को हुआ है परन्तु नगर निगम धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Choephel Kalsang s/o Late Phuntsok का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Subh Karan s/o Sh. Daya Ram, r/o Village Dadal, P.O. Meramasit, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Suman Kumari d/o Sh. Rikhi Ram, r/o Village Ghanghanu, P.O. Ghanghanu, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Subh Karan and Suman Kumari applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-01-2020 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-07-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 09-06-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Deep Kumar s/o Sh. Chandermani, r/o Village Dol, P.O. Batwara, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Nisha Kumari d/o Sh. Babu Ram, r/o Village Tatar, P.O. Batwara, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Deep Kumar and Nisha Kumari applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-11-2019 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-07-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 09-06-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Rakesh Chand s/o Sh. Damodar Dass, r/o Durga Bhawan, Chalaunthi Sanjauli, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Rakesh Chand s/o Sh. Damodar Dass, r/o Durga Bhawan, Chalaunthi Sanjauli, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely PRIYANKA (DOB 05-01-2003) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before, within (30) days from the date of publication of this notice in official Gazette, failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th June, 2020.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अर्जुन शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, वासी गांव अन्दौरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी करने बारे।

श्री अर्जुन शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, वासी गांव अन्दौरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री मदन लाल, गांव दावट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर में दिनांक 06-02-2019 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण—पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 03-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्या: गृह-सी(ए)4-3/2013-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: गृह-सी(एफ)6-1/94 तारीख 5 अगस्त, 2003 के क्रम में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री प्यार सिंह राणा, निवासी हाउस संख्या 133 MIG, टाइप-III-A, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं० 7, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 177001 को, उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English Text of Government Notification No. Home-C(A)4-3/2013-I, dated 23-6-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. Home-C(A)4-3/2013-I.—In continuation of this Department Notification No. HOM-C (F)6-1/94, dated 5th August, 2003, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No.10 of 1994) and on the recommendation of the Committee constituted for the purpose, is pleased to appoint Hon'ble Justice (Retd.) Sh. Piar Singh Rana, resident of House No.133 MIG, Type-III-A, Housing Board Colony, Ward No.7, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh-177001, as the Chairperson of the Himachal Pradesh Human Rights Commission for a period of three years or till attaining the age of seventy years, whichever is earlier, from the date on which he enters upon his office.

The terms and conditions of service of the Chairperson of the Himachal Pradesh Human Rights Commission shall be regulated as per the provisions of the Himachal Pradesh Human Rights Commission (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2020.

By order,

MANOJ KUMAR,
Add. Chief Secretary (Home).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्या: गृह-सी(ए)4-3/2013-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: गृह-सी(एफ)6-1/94 तारीख 5 अगस्त, 2003 के क्रम में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर डॉ० अजय भंडारी, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त), सूरज कुन्ज भवन, सेक्टर-5, न्यू शिमला, हि० प्र० को, उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English Text of Government Notification No. Home-C(A)4-3/2013-I, dated 23-6-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. Home-C(A)4-3/2013-I.—In continuation of this Department Notification No. HOM-C(F)6-1/94, dated 5th August, 2003, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994) and on the recommendation of the Committee constituted for the purpose, is pleased to appoint Dr. Ajai Bhandari, IAS (Retd.), Suraj Kunj Building, Sector-5, New Shimla, H.P. as a Member of the Himachal Pradesh Human Rights Commission for a period of three years or till attaining the age of seventy years, whichever is earlier, from the date on which he enters upon his office.

The terms and conditions of service of the Member of Himachal Pradesh Human Rights Commission shall be regulated as per the provisions of the Himachal Pradesh Human Rights Commission (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules.

By order,

MANOJ KUMAR,

Add. Chief Secretary (Home).